(37)

प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा दिनांक 15.08.2012 को
लाल किले के प्राचरी से राष्ट्र के नाम संदेश

मेरे प्यारे देशवासियो, भाइयो और बहनो और प्यारे बच्चो,

आप सभी को मैं आजादी की सालगिरह पर बधाई देता हूं। (तालियां) महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के हमारे नेताओं ने एक आजाद और खुशहाल भारत का सपना देखा था। सन 1947 में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने लाल किले पर आज के दिन तिरंगा फैहरा कर इस सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम रखा था। (तालियां) जो सफ़र 15 अगस्त, 1947 को हमने शुरू किया, उसको आज 65 साल बीत चुके हैं। इन 65 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है।

आज निश्चय ही भारत के लिए आजादी की कामयाबी का जश्न मनाने का दिन है। लेकिन इस मौके पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या कुछ करना है। (रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई नहीं दे रहा) हमारी आजादी सही मायनों में तभी पूरी होगी जब हम अपने देश से गरीबी, अशिक्षा, भूख और पिछड़ेपन को खत्म कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाएं और अपनी असफलताओं से सबक सीखें।

भाइयो और बहनों, आप जानते हैं कि इन दिनों विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार कम हुई है। यूरोप के देशों को मिलाकर देखा जाये तो इस साल उनकी विकास दर शून्य रहने का अनुमान है। हमारे देश के बाहर के हालात पर असर हम पर भी पड़ा है। साथ ही देश के अन्दर कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो हमारे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रही हैं। पिछले साल हमारी जी0डी0पी0 में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इस साल हमें इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद है।

हम अपने देश के बाहर के हालात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने देश के अन्दर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ताकि हमारे आर्थिक विकास की दर और देश में रोजगार के नये मौके पैदा होने की रफ्तार फिर से तेज हो सके। साथ में हमें मंहगाई पर भी काबू रखना है। इसमें थोड़ी मुश्किल खराब मानसून की वजह से आएगी। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए हमने कई उपाय किये हैं। उन फसलों में, उन जिलों में जहां बरसात में 50 फीसद इससे ज्यादा की कमी हुई है, सरकार किसानों को डीजल सब्सिडी दे रही है। सीड सब्सिडी में बढ़ोत्तरी की गयी है, चारे के लिए केन्द्र की योजना में उपलब्ध राशि बढ़ा दी गयी है। हमारी कोशिश है कि हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में बीज, चारे और पानी की वजह से लोगों को परेशानी न हो। अच्छी

बात ये है कि हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत की वजह से देश में अनाज का बहुत बड़ा भण्डार है और अनाज की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने पैदा नहीं होगी।

भाइयो और बहनो, जहां तक तेज आर्थिक विकास के लिए देश के अन्दर अनुकूल वातावरण बनाने का प्रश्न है, मेरा मानना है कि बहुत से मुद्दों पर आम राजनैतिक सहमति न होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने विकास प्रक्रिया से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की तरह देखें। अगर हम देश के आर्थिक विकास की दर को तेज नहीं करते हैं, अर्थ व्यवस्था में नये निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, सरकार के वित्तीय प्रबन्धन को बेहतर नहीं बनाते हैं और आम आदमी की आजीविका, सुरक्षा और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम नहीं करते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर निश्चिय ही असर पड़ता है।

मेरा आज आपसे वादा है कि हमारी सरकार भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए और देश को विश्वभर में छाये आर्थिक संकट से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। हम शहरों और गांवों में रहने वाले (तालियां) अपने नौजवान भाई–बहनों को रोजगार के नये मौके उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे हमारे गरीब भाई–बहनों, मजदूरों और किसानों की आजीविका सुरक्षित रहे। हम वो हर सम्भव प्रयास करेंगे जिससे हमारे देश में निवेश को बढ़ावा मिले और हमारे उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान कर सकें।

मेरे प्यारे देशवासियो, मेरा मानना है कि हमारी परेशानियों का मौजूदा दौर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इन दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करते हुए हमें इस बात से हौसला मिलना चाहिए कि पिछले आठ सालों में हमने कई क्षेत्रों में असाधारण सफलताएं प्राप्त की हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरह की सफलताएं बहुत से नए क्षेत्रों में भी हासिल करें।

भाइयो और बहनो, पिछल आठ सालों के दौरान हमारी यह कोशिश रही है कि हम अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, ताकि वह राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान दे सकें। आज देश के हर पांच में से एक घर जोब–कार्ड के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से फायदा उठाने का हकदार बन चुका है। सिर्फ पिछले साल में हमने 8 करोड़ से अधिक लोगों को इस स्कीम के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया है।

सन् 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो हमने वादा किया था कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए हमने राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना की शुरूआत की। इस योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक नए गांवों को इलेक्ट्रिकसिटी कनेक्शन से जोड़ा गया है और अब करीब–करीब सभी गांवों में बिजली पहुंच

चुकी है। अब हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाना और बिजली की सप्लाई को बेहतर करना है। (तालियां)

मेरे प्यारे देशवासियो, हमारे मेहनती किसानों की जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। उन्होंने पिछले दो वर्ष में लगातार फसलों का रिकार्ड उत्पादन किया है। कृषि के विकास और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार की कोशिशों के कारण ग्याहरवीं वर्षीय योजना में कृषि में 3.3 प्रतिशत का औसत विकास हुआ, जो दसवें प्लान के 2.4 प्रतिशत की दर से काफी ज्यादा है। पिछले आठ सालों में हमने फसलों का खरीद मूल्य दुगुना कर दिया है। हम लाखों छोटे किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं।

हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद हों और सही शिक्षा पाते हों तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल रहेगा। (तालियां) इसीलिए हमारी सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बच्चों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है। बच्चों की पढ़ाई को कानूनी तौर पर जरूरी बना दिया गया है। सन 2006–07 में 6 से 14 साल के बीच के सिर्फ 93 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे थे। आज इस ऐज ग्रुप के करीबन सभी बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं।

सिर्फ पिछले दो सालों में देश में 51 हजार नए स्कूल खोले गए हैं और तकरीबन साल लाख अध्यापकों को उनमें नियुक्त किया गया है। अब हम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की तरफ खास ध्यान देंगे। अगले कुछ महीनों में हम ऐसा इंतजाम करेंगे जिसमें लगातार यह जानकारी मिलती रहे कि बच्चों को पढ़ाई का कितना फायदा पहुंच रहा है। इसमें समुदाय और बच्चों के मां–बाप की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उनको अपने बच्चों की पढ़ाई से इत्मिनान मिल सके। स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना के जरिए आज देश भर में करीबन 12 करोड़ बच्चे रोज पोष्टिक खाना पाते हैं। यह दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। (तालियां)

पिछले डेढ़ साल में हमारे देश में पोलियो का एक भी नया केस सामने नहीं आया है और अब भारत उन देशों की सूची में शामिल नहीं है, जिनमें पोलियो का असर है। बच्चों में कुपोषण हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने कई क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हैं। आईसीडीएस स्कीम से फायदा उठाने वाली माताओं और बच्चों की तादाद पिछले आठ सालों में दुगुनी हो गयी है। आईसीडीएस स्कीम को और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है और इसे अगले एक दो महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

साल 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था, ताकि देश के हरेक गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। आज इस मिशन को लागू करने के लिए तकरीबन 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिनमें साढ़े आठ लाख आशा कार्यकर्ता

शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कामयाबी के बाद अब हम शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदला जाएगा। यह पूरे देश के सभी गांवों और शहरों में लागू होगा। हम सभी देशवासियों के लिए सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से जरूरी दवाएं मुफ्त देने की एक स्कीम भी बना रहे हैं। (तालियां)

भाइयो और बहनो, हम अपने नौजवानों के लिए आने वाले सालों में रोजगार के बहुत से नए अवसर पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि हम उनको ऐसी स्किल्स में ट्रेनिंग दिलवाएं जिनकी हमारी अर्थव्यवस्था को जरूरत है। हमारा प्रयास है कि हम बहुत सी नई स्किल्स में ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का इंतजाम करें। हम ऐसी व्यवस्था भी करना चाहते हैं जिसमें 6 हफ्ते से 6 महीने तक की अवधि के छोटे ट्रेनिंग कोर्सिस का लाभ हमारे नौजवान भाई–बहन उठा सकें। नेशनल स्किल डिवलपमेंट काउंसिल ने ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है जिसके तहत अगले पांच साल में 8 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो केन्द्र सरकार द्वारा एक खास एजेन्सी बनाकर ही पूरी की जा सकती है।

इसलिए हम एक नेशनल स्किल डिवलपमेंट अथोरिटी की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं ताकि स्किल डिवलपमेंट के कार्यक्रमों को सारे देश में तालमेल के साथ लागू किया जा सके। इस काम में सरकार के अलावा निजी कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान भी जरूरी होगा।

उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर ही हम रोजगार के लिए नए और बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार करना होगा। हमने हाल ही में इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाने के लिए नए उपाय किए हैं। सड़क, बंदरगाह, रेल, बिजली और कोयला के क्षेत्रों में नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाएगी। विदेशी पूंजी को भारत में लाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भरोसा पैदा करना होगा कि भारत में निवेश में कोई रूकावतें नहीं हैं।

भाइयो और बहनो, सिर्फ दस साल पहले तक हमारे गांवों में दस में से सिर्फ तीन घर बैकिंग सेवाओं से जुड़े थे। आज आधे से भी ज्यादा ग्रामीण घरों में बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले दो सालों में सभी घरों को बैंक खातों का लाभ मिल पाए। हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि जिसमें सरकारी स्कीमों से जारी पैसा जैसे – बुजुर्गों की पेंशन, छात्रों की स्कोलरशिप और मजदूरों का मेहनताना, सभी का भुगतान सीधे लोगों के बैंक एकाउंट में किया जाए। इससे लोगों की परेशानी कम होगी, वो आसानी से भुगतान पा

(41)

सकेंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बड़े काम के लिए हम आधार स्कीम का सहारा लेंगे, जिसमें अब तक लगभग 20 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। (तालियां)

देश के शहरी इलाकों में रहने वाले अपने गरीब भाई–बहनों को मकान मुहैया कराने के लिए हम शीघ्र ही राजीव आवास ऋण योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लोगों को मकान बनाने के लिए 5 लाख रूपये तक के कर्ज पर ब्याज में छूट दी जाएगी।

भाइयो और बहनो, इसी साल हम बारहबीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रखेंगे। योजना में देश के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे की कार्रवाई को तय किया जाएगा। इसमें उन उपायों का निर्धारण किया जाएगा जिनसे हमारे आर्थिक विकास की दर वर्तमान 6.5 प्रतिशत से बढ़कर योजना के आखिरी साल में 9 प्रतिशत हो पाए। योजना में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो देश के विकास का फायदा भारत के हर नागरिक तक और खासतौर पर कमजोर तबकों तक पहुंचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बारहबीं योजना को केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।

भाइयो और बहनो, अभी हाल में असम में हिंसा की जो घटनाएं हुईं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे यह अहसास है कि इन घटनाओं से एक बड़ी तादाद में लोगों की जिन्दगी अस्त–व्यस्त हो गयी है। हिंसा से प्रभावित परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम उनको राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे यह भी वायदा है कि हमारी सरकार इन घटनाओं की वजहों को समझने की पूरी कोशिश करेगी और राज्य सरकारें के साथ मिलकर मेहनत से काम करेगी, ताकि देश में कहीं भी इस तरह के हादसे दोबारा न होने पायें।

आंतरिक सुरक्षा के कई क्षेत्रों में हमें सफलताएं मिली हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनावों में लोगों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा में कमी आई है और वहां के कई गुटों के साथ हमारी बातचीत जारी है, ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा में फिर से शामिल किया जा सके।

नक्सलवादी इलाकों में हमने विकास की कई नई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वहां के लोगों की और खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई–बहनों की, शिकायतें दूर की जा सकें और उनकी हालत में सुधार हो सके। लेकिन आंतरिक सुरक्षा के विषय पर हमें लगातार चौकस रहने की जरूरत है। सांप्रदायिक सद्भाव को हमें हर कीमत पर बनाए रखना है। नक्सलवाद अभी भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इस महीने के शुरू में पुणे में जो

42

घटनाएं हुईं, वे इस बात की तरफ इशारा करती है कि आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमें अभी भी काफी काम और करना है। यह काम हम आगे भी लगन और मेहनत के साथ करते रहेंगे।

मेरे देशवासियो, मैं अपने वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजिस्ट्स को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस साल अग्नि–5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके और रिसेंट–1 उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलता से छोड़कर भारत की शान बढ़ाई है। अभी हाल ही में हमारी कैबीनेट ने मार्स आर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पास जाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करेगा। यह मंगलयान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारे लिए एक बड़ा कदम होगा। (तालियां)

भाइयो और बहनो, हमने हाल के महीनों में अपनी सेना की भूमिका और उसकी तैयारी के बारे में काफी बहस देखी। मैं, इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारी फौज और हमारे अर्द्ध सैनिक बलों ने शांति और युद्ध के समय हमारे देश की हिफाजत, सम्मान और बहादुरी के साथ की है। जब कभी भी जरूरत हुई है, हमारे सैनिकों ने बड़े से बड़ा बलिदान दिया है। आज, मैं अपने सभी देशवासियों को एक बार फिर यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारी सेना और अर्द्ध सैनिक बल हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

सरकार इन बलों को आधुनिक बनाने के लिए वचनबद्ध है और उन्हें जरूरी टैकनोलॉजी और साजो–सामान मुहैया करवाने का काम जारी रखेगी। आज के दिन मैं अपने सुरक्षा बलों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो जांबाजी से हमारी सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनकी भलाई के लिए बराबर काम करते रहेंगे। हमारी सरकार ने सेना के सैनिकों और अफसरों के वेतन और पैंशन संबंधी मामलों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति रिटायर सैनिकों और अफसरों की पैंशन और उनके परिवारों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगी। समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद हम उन पर जल्द से जल्द फैसला करेंगे। (तालियां)

मेरे प्यारे देशवासियो, हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के दूसरे पिछड़े तबकों की भलाई पर विशेष ध्यान दिया है। हमारे देश के आदिवासी और पिछड़े जिलों की तरक्की की खास जरूरतों को इन्टीग्रेटिड एक्शन प्लान, बैकवर्ड एरियाज ग्रान्ट फंड्स और ट्राइबल सब प्लान जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए पूरा किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम के तहत हमने अनुसूचित जनजाति के लाखों भाई–बहनों को इस जमीन पर मालिकाना हक दिया है जिस पर वह पीढ़ियों से रह रहे हैं। हम एक ऐसी योजना भी बना रह हैं जिसके जरिए जनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनके द्वारा इकट्ठा किए गए वन उत्पादों के अच्छे और वाजिब दाम मिल सकें। सरकार, माइन्स और मिनरलस, डिवलपमेंट एण्ड रेगुरेशन बिल को जल्दी अमल में लाना चाहती है। इस कानून के जरिए हम

(43)

माइनिंग वाले क्षेत्रों में अपने आदिवासी भाई बहनों के फायदे के लिए धन उपलब्ध कराना चाहते हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए 15 सूत्री कार्यक्रम को हम अधिक प्रभावी बनाएंगे। ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में लागू किए जा रहे मल्टी सैक्टोरल डिवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तार किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलने वाले पोस्ट मैट्रिक वजीफों की दरों में हमने बढ़ोत्तरी की है। इन तबकों को मिलने वाले वजीफों की व्यवस्था को अधिक कारगर बनाने की हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। (तालियां) सरकार एक नया और प्रभावी कानून बनाने पर विचार कर रही है ताकि हाथ से मैला उठाने के घिनौने चलन को बंद किया जा सके और इस काम में लगे लोगों को नई ज़िंदगी बसर करने का मौका मिल सके।

भाइयो और बहनो, सरकार और प्रशासन के काम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का हमारा संकल्प बरकरार है। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत से कदम उठाएगी। मुझे आज यह कहते हुए खुशी है कि पिछले एक साल में इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है।

लोकसभा ने लोकपाल ओर लोकायुक्त बिल पास कर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल को पास करने में सभी राजनैतिक दल हमारी मदद करेंगे। कई और बिल भी संसद में पेश किए जा चुके हैं। कैबिनेट ने एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। लोक सेवकों के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और उसमें भ्रष्टाचार कम करने की कोशिशें हम जारी रखेंगे। लेकिन हम यह भी ध्यान रखेंगे कि इससे राष्ट्रहित में फैसले लेने वाले अधिकारियों के मनोबल को बे–बुनियाद शिकायतों ओर गैर–ज़रूरी अदालती कार्रवाइयों से नुकसान न पहुंचे।

भाइयो और बहनो, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने राष्ट्र के नाम अपने पहले ही संदेश में आप सभी से राष्ट्रनिर्माण के महान काम में योगदान करने की अपील की थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज पहले से कहीं ज्यादा संख्या में हमारे देश के नागरिक और विशेषकर नौजवान समाज और देश की प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारी सरकार मानती है कि भारत के सामने जो कठिन समस्याएं हैं, उनका मुकाबला हम आम आदमी के सहयोग से ही कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में और बड़ी संख्या में लोग गरीबी, अशिक्षा और असमानता दूर करने जैसे कामों में हमारी सहायता करें।

भाइयो और बहनो, मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे महान देश को विकास और तरक्की की नई ऊचाइयां पाने से नहीं रोक सकती। जरूरत सिर्फ इस बात की

44

है कि हम सब मिलजुलकर और एक होकर अपने देश की कामयाबी के लिए काम करें। आइए, एक बार फिर ये प्रण करें कि हम सब एक प्रगतिशील, आधुनिक और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए लगातार काम करते रहेंगे।

अंत में, प्यारे बच्चो, मेरे साथ मिलकर तीन बार बोलिए जय हिन्द।

जय हिन्द ! (जय हिन्द)

जय हिन्द ! (जय हिन्द)

जय हिन्द ! (जय हिन्द)